

IPCC AR6 सथिससि रपिर्ट

प्रलिमिस के लयि:

IPCC, जलवायु परविरतन, ग्लोबल वारमगि, GHG, CCH, कुरूपता

मेन्स के लयि:

IPCC AR6 सथिससि रपिर्ट ।

चर्चा में क्यो?

छठी आकलन रपिर्ट (Sixth Assessment Report- AR6) के तहत [जलवायु परविरतन पर अंतर-सरकारी पैनल \(Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC\)](#) की चौथी और अंतिम रपिर्ट के अनुसार, कई क्षेत्रों और स्थानों में पर्यावरण को पर्याप्त रूप से समायोजित करने में वफिलता के अधिक प्रमाण मिले हैं ।

- सथिससि रपिर्ट तीन कार्य समूहों और तीन विशेष रपिर्टों के योगदान के आधार पर AR6 चक्र के प्रमुख नषिकर्षों का संश्लेषण करती है ।






प्रमुख बढि

- **अभूतपूर्व ग्लोबल वारमगि:**
 - मानव गतविधियों के कारण [ग्लोबल वारमगि](#) में 1.1 डगिरी सेल्सियस की वृद्धि ने जलवायु परविरतन को प्रेरित किया है जो हाल के मानव इतहास में अभूतपूर्व है ।
 - पहले से ही वैश्विक तापमान में 1.1 डगिरी सेल्सियस की वृद्धि के साथ जलवायु प्रणाली में परविरतन जो सदियों से सहस्राब्दियों तक अद्वितीय रहे हैं, के कारण अब दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में समुद्र के बढ़ते स्तर से लेकर अधिक [चरम मौसम की घटनाओं](#) एवं तेज़ी से समुद्री बर्फ पघिलने की घटनाएँ देखी जा रही हैं ।
- **अधिक व्यापक जलवायु प्रभाव:**
 - लोगों और पारसिधितिक तंत्रों पर [जलवायु के प्रभाव](#) अनुमानित स्तर से अधिक व्यापक और गंभीर हैं, भवषिय के खतरे वारमगि की हर मामूली तीव्रता अथवा स्तर के साथ तेज़ी से बढ़ेंगे ।
- **अनुकूलन के उपाय:**
 - अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से सुनम्यता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है, **परंतु इसके लयि अधिक धन की आवश्यकता होती है ।**
 - कम-से-कम 170 देशों में जलवायु नीतियाँ अब अनुकूलन को प्राथमिक उपाय मानती हैं, लेकिन कई देशों में योजना से लेकर क्रयिन्वयन तक इन पर्यासों को कयि जाने की आवश्यकता है । सुनम्यता बढ़ाने के अधिकांश उपाय अभी भी छोटे पैमाने के तथा प्रतिक्रयिशील और वृद्धिशील हैं, जो मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रभावों अथवा खतरों पर केंद्रित होते हैं ।
 - अनुकूलन के लयि वर्तमान वैश्विक धन प्रवाह, विशेष रूप से विकासशील देशों में अनुकूलन समाधानों के कार्यान्वयन के लयि अपर्याप्त हैं ।
- **वैश्विक तापमान 1.5 डगिरी सेल्सियस पार कर सकता है:**
 - अध्ययन कयि गए परदृश्यों को देखते हुए **इस बात की 50% से अधिक संभावना है कविरष 2021 और 2040 के बीच वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डगिरी सेल्सियस तक पहुँच जाएगी या उससे अधिक भी हो सकती है ।** वर्तमान उच्च-उत्सर्जन स्तर को देखते हुए यह वर्ष 2037 तक ही इस सीमा तक पहुँच सकती है ।
- **दर अनुकूलन:**
 - भारत में दर अनुकूलन के ऐसे कई उदाहरण हैं, जसिके परिणामस्वरूप कमज़ोर समुदाय जलवायु परविरतन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन करने में सक्षम होने के बजाय अधिक असहाय हो जाते हैं ।
 - दर अनुकूलन को प्राकृतिक या मानव प्रणालियों में परविरतन के रूप में परिभाषित किया गया है जो अनजाने में जलवायु उत्तेजनाओं के प्रति भेद्यता को बढ़ाता है ।

- यह एक अनुकूलन उपाय है जो भेद्यता को कम करने में सफल नहीं होता है बल्कि इसके बजाय इसे बढ़ाता है।
- ओडिशा देश के सबसे सक्रिय तटों में से एक है, जहाँ **समुद्र का जल स्तर** देश के बाकी हिस्सों के औसत से अधिक दर से बढ़ रहा है। यह भारत में सबसे अधिक चक्रवात-प्रवण राज्य भी है।

40% OF INDIANS WILL FACE WATER SCARCITY BY 2050

What does the IPCC report mean for India?

 <ul style="list-style-type: none"> > An increase in annual mean precipitation is projected 	<p>India is expected to see an increase in frequency and severity of hot extremes</p>	<ul style="list-style-type: none"> > By the middle of the century, around 35 million people in India could face annual coastal flooding
<ul style="list-style-type: none"> > Increase in rainfall will be more severe over southern parts of India 	 <p>Forest fire incidents may rise due to increased heat waves condition</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Economic costs of sea-level rise and river flooding for India would also be among the highest in the world
<ul style="list-style-type: none"> > Rainfall could increase by around 20% on the southwest coast compared to 1850-1900 level 		<ul style="list-style-type: none"> > Direct damage is estimated at between \$24 billion if emissions are cut only about as rapidly as currently promised
 <ul style="list-style-type: none"> > Monsoon precipitation is projected to increase in the mid- to-long term over South Asia 	<p>experiencing more heat stress, urban floods, salinity ingress due to sea-level rise and other climate-induced hazards such as cyclones</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Climate change and rising demand mean that about 40% of people in India will live with water scarcity by 2050 compared with about 33% now
<ul style="list-style-type: none"> > Rising temperature and precipitation can increase the occurrence of glacial lake outburst floods and landslides over moraine-dammed lakes 	 <ul style="list-style-type: none"> > India is one of the most vulnerable countries globally in terms of the population that will be affected by sea-level rise. (Cities to be affected: Mumbai, Kolkata, Chennai, Goa, Cochin and Puri among others) 	<ul style="list-style-type: none"> > Both the Ganges and Brahmaputra river basins will also see increased flooding as a result of climate change, particularly if warming passes 1.5°C
 <ul style="list-style-type: none"> > Snowline elevations will rise and glacier volumes will decline 		<ul style="list-style-type: none"> > Productivity of food crops, including maize, will be affected
<ul style="list-style-type: none"> > Regional mean sea level will continue to rise 		
<ul style="list-style-type: none"> > Cities in India will be 		

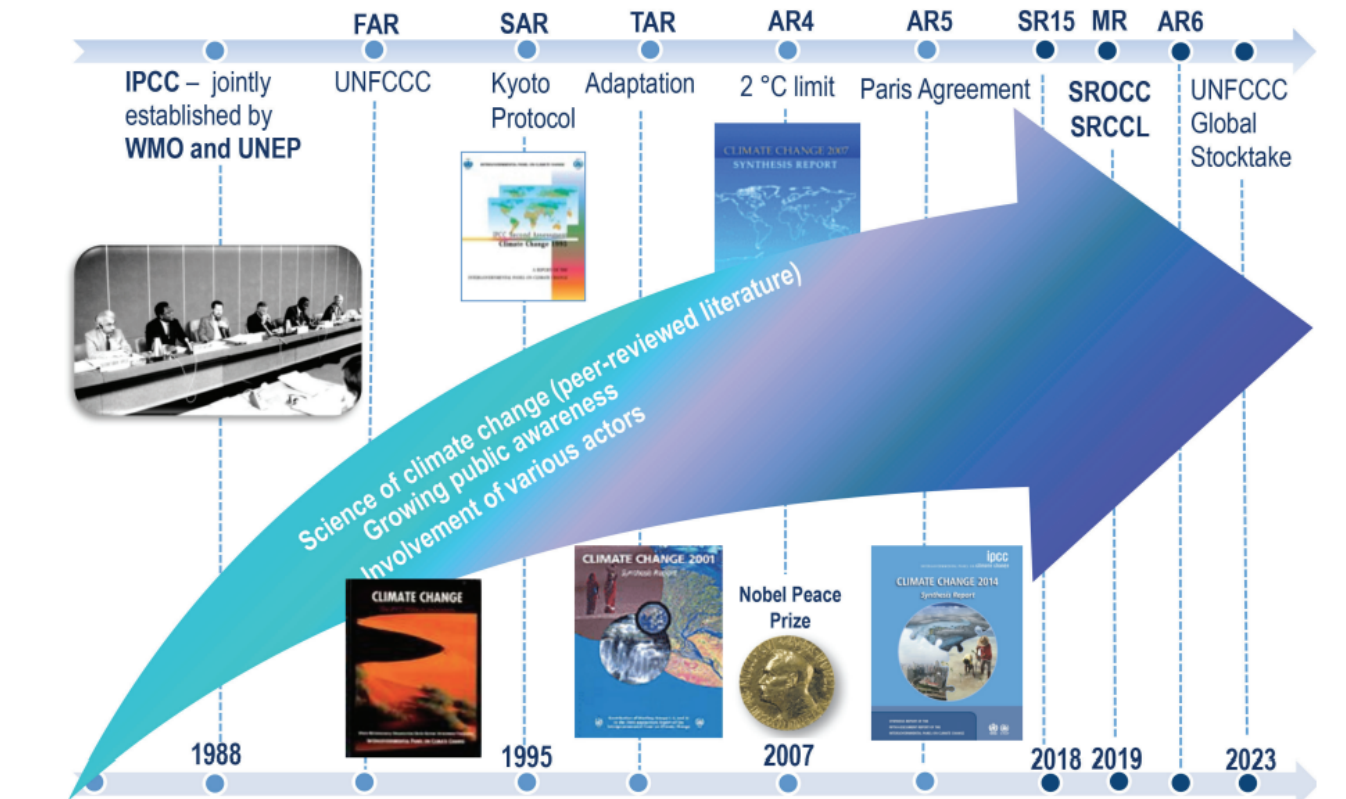
सफ़ारिशें:

- विश्व को जलद-से-जलद जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करना होगा क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलवायु संकट का प्रमुख कारण है।
- मौजूदा **जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढाँचे को समाप्त करने**, नई परियोजनाओं को रद्द करने, **कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS)** प्रौद्योगिकियों के साथ जीवाश्म ईंधन वाले वदियुत संयंत्रों को पुनः संयोजित करने तथा सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने जैसी रणनीतियों का एक संयोजन, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद कर सकता है।
- शुद्ध-शून्य, जलवायु-परिवर्तन संबंधी भवषिय को सुरक्षित करने के लिये तत्काल प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता है।
- जबकि जीवाश्म ईंधन ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। जलवायु संकट से निपटने के लिये उत्सर्जन में भारी कटौती आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC):

- IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है।
- यह 1988 में **विश्व मौसम विज्ञान संगठन** और **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** द्वारा नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार, इसके प्रभावों एवं भवषिय के जोखिमों तथा अनुकूलन व शमन के विकल्पों के नियमित आकलन हेतु स्थापित किया गया था।

IPCC contribution to climate science and policymaking



स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ipcc-ar6-synthesis-report>